सरकार के प्रतिनिधि वेबिनार में आए तो हमारी बात आसानी से पहुंची

बोले बिल्डर्स : पत्रिका ने किया सेतु का काम

पत्रिका मंच

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. जयपुर. पत्रिका के संवाद सेतु कार्यक्रम को बिल्डर्स ने काफी सराहा है। वेबिनार के जरिए राज्य भर के बड़े बिल्डर्स और डवलपर्स ने कोरोनाकाल में आ रही दिक्कतों को सरकार के सामने रखा। खुद नगरीय विकास विभाग के सलाहकार जीएस संधु ने स्वीकार किया कि मुझे भी बिल्डर्स से मिलकर उनकी समस्याओं को समझना था, लेकिन समय की कमी होने से मिल नहीं पा रहा था। पत्रिका ने सेतु का काम किया है और सभी बिल्डर्स ने अपनी बात रखी है। इनकी समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा।

अधिकतर बिल्डर्स और डवलपर्स का भी यही मानना था कि कोरोनाकाल में पत्रिका ने सरकार से नियमित रूप से संवाद कराने का काम किया। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल से लेकर विभाग के अधिकारी वेबिनार में जुड़े और समस्याओं को समझा और उनको दूर भी किया जा रहा है।

फॉलोअप

रियल एस्टेट से जुड़े कई सेक्टर, सरकार की बढ़

राजस्थान पत्रिका

प्रकाशित खबर।

ये आए सुझाव

- रियल एस्टेट से जुड़े मजदूरों के लिए जन आधार कार्ड की तरह अम्बेडकर कार्ड बनाए जाएं।
- अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत बिल्डर और डवलपर्स को मिलने वाले टीडीआर का लाभ मिले।
- प्रोजेक्ट की बेवजह आपत्तियों का निस्तारण तय समय में ही कर दिया जाए।

कई जगह सर्कल रेट मार्केट रेट से अधिक है। सरकार को सर्कल रेट कम करनी चाहिए। इससे जमीन की बिक्री ज्यादा होगी और सरकार को भी ज्यादा स्टाम्प ड्यूटी का कलेक्शन होगा। **-अर्पित गोयल,** निदेशक, सनसिटी प्राजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

सब डिवीजन की अभी लिमिटेड ऑथोरिटी है। इससे प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है। इसमें थोड़ी तेजी दिखानी चाहिए, ताकि प्रोजेक्ट तय समय में पूरे हो सकें। **-ओम माहेश्वरी,** एमडी, उपासना ग्रुप

रियल एस्टेट को सरकार ने प्रोत्साहित किया है। घर के लिए स्टाम्प ड्यूटी और जीएसटी दोनों देना पड़ता है। जो पूरी कीमत का 15 फीसदी होता है। सहूलियत मिले तो लोगों को कम दर पर मकान मिल सकता है। **-विनोद गोयल,** निदेशक, मंगलम बिल्डर्स

व्यवसायिक प्रॉपर्टी में कोरोना के बाद से बूम आना शुरू हुआ है। आने वाले कुछ महीनों में इसमें और चढ़ाव देखने को मिलेगा। इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। **-राजेश यादव,** एमडी, आर-टेक ग्रुप

शिवदासपुरा में एयरपोर्ट तो निरस्त हो गया, लेकिन वहां की 5000 बीघा जमीन पर यदि इंडस्ट्री को विकसित किया जाए तो रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। **-रामबाबू अग्रवाल,** निदेशक, मंगलम बिल्डर्स

जेडीए की रिजर्व प्राइज ज्यादा है। इसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। नियमन योग्य निर्माणों को शुल्क लेकर अभियान में पट्टे दिए जाने चाहिए। **-कमल सेठिया,** एमडी, वर्द्धमान ग्रुप

मास्टरप्लान की सेक्टर रोड की रुकावटों को दूर कर व्यवस्थित किया जाए। इससे शहर में व्यवस्थित विकास होगा और लाखों लोगों को राहत भी मिलेगी।

-सीके मित्तल, एमडी, टीम आरआरसी

कोरोना के बाद से नगरीय विकास विभाग और सरकार से काफी राहत मिली है। इससे सेक्टर को आगे बढ़ने में मदद मिली है। उम्मीद है ऐसा सहयोग आगे भी मिलता रहेगा।

-सिद्धार्थ गुप्ता, कंसल्टेंट, उन्नति ग्रुप

कोरोना के बाद रियल एस्टेट बड़ी दिक्कत में है। सरकार ने काफी सहूलियत दी है। यदि थोड़ी राहत और मिल जाएगी तो ये सेक्टर तेजी से चल निकलेगा।

-आशीष चौधरी, निदेशक, आशीष ग्रुप

अफोर्डेबल हाउसिंग में महंगी दर पर लोन मिलता है। इससे जरूरतमंदों को घर खरीदने में दिक्कत होती है। इसमें सरकार राहत दे तो जरूरतमंदों को आवास मिल सकेंगे। **-मनमोहन,** निदेशक, एबीपी इन्फ्रा